when we talk about the children, whether it is Muslim or downtrodden, children are taken as a source of income. This may not be directly related to hon. Minister's Ministry, but I would like to know if there is something being done. Children are used to go out for earning. That is one aspect. The other aspect is, in order to give opportunity to Muslim women or downtrodden, you do require teachers. Sir, I would like to know whether there are any schemes to train the teachers, especially to teach this class of our society.

डा. मुरली मनोहर जोशीः सभापति जी, जहां तक इस बात सवाल है कि जिन बच्चों को पढ़ने के लिए अध्यापकों और अध्यापिकाओं की आवश्यक्ता हैं, मूलतः शिक्षक प्रशिक्षण का काम राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन हमारी कोशिश भी रहती है और हम उनको बार-बार बताते भी रहते हैं कि इस प्रकार की आवश्यकता हैं आप इस काम को करें। हम बार-बार इसका आग्रह करते हैं, और कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह काम राज्य सरकारों के अधीन होने की वजह से उसकी प्रगति की दर पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन इस बात में वजन है और हम इसको स्वीकार करते हैं कि इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की वृद्धि होनी चाहिए और हम राज्य सरकारों को फिर से लिखेंगे कि इस तरफ वे पूरा ध्यान दें।

*424. [The questioners (Shri Kapil Sibal and Shri Ram Jethmalani) were absent. For answers *vide* page 33-34 *infra.]*

National Programme for Education of Girls

*425. SHRIMATI SHABANA AZMI :†

DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have cleared the ambitious National Programme for Education of Girls at the elementary level;

(b) if so, the details of the programme;

(c) what is the total amount set for this purpose;

(d) by what time the programme is likely to be implemented; and

(e) the States where this programme is likely to be introduced?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Shabana Azmi.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. SANJAY PASWAN): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) The Government of India has approved a new programme called 'National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL)' as an amendment to the existing scheme of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) for providing additional components for education of girls at elementary level. The NPEGEL will form part of SSA and will be implemented under the umbrella of SSA but with a distinct identity.

The scheme would provide the following additional components under SSA:— (i) to develop a school at cluster level, as a model girl-child friendly school; (ii) additional incentives such as stationery, slates, work books, uniforms and/or to meet any other locally felt need within the existing ceiling of Rs. 1507-per child per annum; (iii) additional interventions like awards to schools/teachers, student evaluation, remedial teaching, bridge courses, alternative schools, learning through open schools, teacher training and child care centres at the cluster level within a ceiling of Rs. 60,000/ per annum; (iv) mobilisation and community monitoring within a ceiling of Rs. 95,000/- per cluster over a five-year period (v) development of materials; as well as (vi) planning, training and management support.

For implementation of the above programme an estimated expenditure amounting to Rs. 1064.80 crores has been kept for the Tenth plan period.

The scheme is slated for implementation from 25th Septemeber, 2003.

The Scheme will be implemented in Educationally Backward Blocks (EBBs) where the level of rural female literacy is less than the national average and the gender gap is above the national average, in blocks of districts which are not covered under EBBs but are having atleast 5% SC/ST population and where SC/ST female literacy is below 10% and also in select urban slums. Based on 1991 Census data, the scheme would cover Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttaranchal and West Bengal. Once the data for 2001 Census become available, selection of blocks will be modified according to the revised data.

SHRIMATI SHABANA AZMI : Sir, the intention to implement the National Programme for Education of Girls at Elementary level as a separate and distinct girl component plan by making suitable amendments to the existing scheme of Sarva Shiksha Abhiyan needs to be lauded and I appreciate it. However, let us look at the ground realities. There is a shortage of 11 lakh primary school teachers in the country. The conditions of the school buildings are dilapidated. Thousands of schools do not have water and sanitation. Now under the Sarva Shiksha Abhiyan any space will be fine, even an open park, as long as we do not have to provide a vibrant, functioning Government school across the street, that will give *Shiksha,* not merely *Saksharta.* This is virtually institutionalising cheap, inferior stopgap arrangement. Creating such parallel systems while the formal systems languish, will cause permanent irrepairable damage. Equitable quality education never reached the approximately, 100 million children currently out of schools, both boys and girls. Now, even poor parents in rural areas want to send their children to schools. But, when they see that the children are not learning anything, particularly, girls, they pull them out of schools. I would like to give an example of a village -MIJWAN -in which I work in Azamgarh, where a woman came up to me and said, आपके कहने पर मैंने अपनी बेटी को स्कूल तो भेज दिया, लेकिन वहां वह कुछ पढ़ नहीं पाई है, जो उसकी जिंदगी से ताल्लुक रखता है या कोई रिलेवेन्स है, इससे तो अच्छा है कि वह मेरे घर पर मेरा हाथ बंटाती। मैं अकेली जान आठ लोगों की देखभाल करती हूं। मेरी बेटी जाकर जो है दूध बेच आती थी। आपके कहने पर मैंने उसे स्कूल भेज दिया। अब वह स्कूल में क्या कर रही है? आपने तो मेरी दुविधा बढ़ा दी है। क्या जवाब है आपका इस पर ?यही सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी।By sacrificing quality education, how do you expect to give rural children equality of opportunity? अभी तो कुछ भी नहीं है। इससे तो बेहतर है कुछ भी मिल जाए। simply is not good enough. It is not as if there is a shortage of funds. The UN Convention of Dakar, on the Fast Track on Education, has said, "Any country that gives us an application with a clear, stipulated programme of action will get these funds." So, through you, I wish to ask the hon. Minister when the Parliament unanimously agreed to spend an additional amount of Rs. 9,800 crores per annum, why have you allocated only Rs. 1,200 crores during the 2002-03 and Rs. 3,500 crores for the year 2003-04?

डा. संजय पासवान : आदरणीय सभापति महोदय, यह हर्ष की बात है कि महिलाओं में साक्षरता बढ़े, यह चिंता सभी माननीय सदस्य कर रहे हैं। जिस ढंग से सर्व शिक्षा अभियान का इस देश में जबसे लांचिंग हुआ है, तब से लोगों में एक आशा जगी है, उम्मीदें बढ़ी हैं। यह केवल इस डिपार्टमेंट की नहीं, यह सरकार की एक फ्लेक्सिबल स्कीम है। यह मिशन स्वयं प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसमें महिलाओं के लिए और जो अभिवंचित वर्ग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, उनके लिए चिंता हो, इसका बराबर इस सरकार ने ध्यान रखा है। खासकर के जो इस संबंध में माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है, उसमें यह 1064 करोड़ रुपए का प्रावधान केवल बालिकाओं की शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान में घटक के रूप में, एक कंपोनेंट के रूप में किया गया है। अभी भी इस देश में यह संख्या ढाई करोड़ के आसपास ऐसी है, जहां स्कूल से बाहर बच्चे हैं। पहले तो इनका इनवोल्वमेंट हो जाए, इन्वोल्वमेंट के बाद वे बच्चे स्कूल में रिटेन करें, यह लक्षय बनाया गया है। क्वालिटी आफ एजुकेशन इसके बाद की स्टेज है। इसलिए हम सब लोग चिंतित हैं बच्चों के इन्वोल्मेंट, रिटेंशन को लेकर। इस वर्ष 2003 के दिसंबर तक हम इस स्टेज में होंगे कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे, सब का नामंकन इस वर्ष के दिसंबर अंत तक हो जाएगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास और आशा है इसके साथ ही साथ पांच वर्ष तक इसके रिटेंशन का है यानि जो प्राइमरी एजुकेशन है वह पूरी हो, फिर वर्ष 2008 तक हम सब लोग उसकी एलीमेंटरी एजुकेशन पूरी हो जाए उस ओर प्रयास कर रहे हैं। उसकी एजुकेशन क्वालिटी बढ़े और जो रिलेवेंट एफेक्टिव एजुकेशन है वह बढ़े, इसका प्रयास हम करेंगे, लेकिन यह बाद की स्टेज है। यह सरकार बिल्कुल चिंतित है, इसके लिए कंसर्नड है और हम लोग माननीय मंत्री जोशी जी को और प्रधान मंत्री जी को बधाई देते हैं कि इन्होंने चिंता जाहिर की। इस ओर माननीय सदस्य और माननीय सदस्यगण भी चिंता कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें उनका समर्थन हमें मिलता रहेगा। हम उनसे केवल यह आग्रह करेंगे कि जो हमारा सिस्टम आफ प्रोग्राम है, जैसे आल्टरनेटिव एजुकेशन हैं, इनोवेटिव एजुकेशन है, उसमें माननीय सदस्य रुचि लें और रुचि लेकर अपने स्तर से और जो भी वहां की चुनी हुई बॉडी हैं, निकाय हैं, एनजीओस हैं, उनको भी इस काम में लगाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।

श्रीमति शबाना आजमी : सर, मेरा सवाल यह था।

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): सभापति जी, आपने जो सवाल उठाया था कि बच्ची वहां जाकर क्या करेगी, यह अहम सवाल है और इसीलिए इसके अंदर एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यह रही है कि इस स्कीम में जहां कलस्टर में स्कूल बनेंगे, वहां एक विशेष व्यवस्था की गई है कि वहां ऐसी शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे बच्चियों की माताओं का इस बात का समाधान हो सके। हमने इसके लिए उन्हें सुविधा दी है कि अपने क्षेत्र की योजनाओं को पहचान कर कहीं पर बच्चियों को संगीत, कहीं पर दस्तकारी, कहीं पर और भी कोई ऐसी

वोकेशन सिखा सकते हैं। यह सुविधा हमने उनको दी है ताकि वह यह काम कर सकें, जो कलस्टर स्कूल बने हैं। अब एक ब्लॉक में करीब इस तरह के सात-आठ स्कूल प्रत्येक ब्लॉक के अंदर बन जाएंगे। वहां जो बच्चियां जाएंगी उनके लिए वहां एक ऐसा कमरा रखा गया है, जिसमें अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया जा सके, मल्टीपरपज रूम दिया गया है, उसके लिए दो लाख रुपए विशेष रूप से दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कि इस तरफ चिंता नहीं है। यह कहना कि धन की कमी है, हां, धन कम है। देश में 50 साल से जो हालत थी धन की, उसके आधार पर जो हम कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में इन्वेस्टमेंट का यह विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। आपने डाकार कन्वेंशन का सवाल उठाया। माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन देशों ने बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएं की थीं और वचन दिए थे कि हम डेवलपमेंट के लिए बहुत सा धन देंगे और .7 परसेंट जीडीपी देंगे, कोई दे नहीं रहा है हम जानते हैं कि उसकी असलियत क्या है। अपने देश की शिक्षा के लिए हमारा यह संकल्प है कि हम अपने बच्चो को अपने साधनों से पढ़ाएं। अब क्वालिटी का मतलब यह नहीं है कि जो इंग्लैंड में हो रहा है, वही हमारे देश में करें। हमारी क्वलिटी उसके बाद भी आज बहुत अच्छी है, हम वहां के स्कूलों के बच्चों के स्तर को देखते हैं। अभी वहां से विशेषज्ञ आए थे और उन्होंने लोगों का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा, This is fantastic." हम नहीं समझ सकते कि इस तरह के विद्यालयों में भी आप ऐसी क्वालिटी पैदा कर रहे हैं। So, quality does not go by building; quality does not go by teaching and learning materials, as designed by the Westerners, हिन्दुस्तान की अपनी एक प्रतिभा है, मेधा है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है अगर हमारे यहां बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। सवाल यह है कि वे क्या पढ़ते हैं, किसलिए पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भवन से शिक्षा का ताल्लुक नहीं है, अध्यापक से शिक्षा का ताल्लुक है और उस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हिन्दुस्तान में क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन की कमी है। आज सारी दुनिया में हमारी ऐजुकेशन की धूम मची हुई है। इसलिए इस हीन-भावना से हमको मुक्त हो जाना चाहिए।

SHRIMATI SHABANA AZMI : Sir, my question was that why even after Parliament had unanimously agreed to spend an additional amount of Rs. 9,800 crores per annum, only an amount of Rs. 1,200 crores had been allocated during the year 2002-03, and Rs. 3,500 crores during the year 2003-04?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: That you see as the first tranche of the Budget. Now, the Revised Estimates are coming up, and we will take into account other requirements of this country. There is a large amount of participation from the public, who are also coming forward. So, you should not be scared about this fact that only Rs. 3,500 crores have

been allocated. Yes, that was the provision in the preliminary Budget. But we are taking up this issue with both, the Planning Commission and the Ministry of Finance. We are hopeful that the requisite amount will come forth.

SHRIMATISHABANA AZMI: Sir, it has, time and again, been pointed out that the Mid-day Meal Scheme has acted as a great incentive for children, particularly the girls in schools. A recent study estimates that the provision of mid-day'meal in schools is associated with 50 per cent reduction in the proportion of girls from out of schools. Now, in spite of the Supreme Court's Judgement, there are several States that continue not to provide cooked mid-day meals, on the plea that they do not have adequate funds. The Centre says that it cannot provide any more funds. So, the person who suffers is the poor child, who is out of the school. We have 64 million tonnes of foodgrains in our granaries, which is being eaten up by rats, while to provide mid-day meals to all the children in schools, it requires only between 2-4 million tonnes of foodgrains. So, my second supplementary is what efforts is the Government making to strengthen the administrative capacity and political will, and ensure that all the States implement the orders of the Supreme Court, and provide good quality mid-day meals to children?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, we are taking up this issue with the State Governments, almost every month. We are advising them, and sometimes even pressing them, and helping them in all ways. I would be very happy to inform this House, once again, that we are involving every community, in this case. There is an experiment by the ISKCON, which is now, feeding about one lakh students, of the schools. There are various other institutions also, which have come forward. Now, the result has been that the State of Tamil Nadu, which was already introducing this scheme, the State of Gujarat, the State of Andhra Pradesh, the State of Karnataka, the State of Rajasthan, have come forward to provide cooked mid-day meals. But it takes time to provide meals to the children in six lakh schools; and now, more so, after schools are being opened under the *Sarva Shiksha Abhiyan,* it needs a lot infrastructure. Many of the States, like West Bengal, are not in a position to do it. What can I do about it? We are giving them whatever we can. Let them come forward with their proposals. Let them strengthen their own infrastructures. The Centre will not, in any case, be having any

difficulty to help them. But the point is that this is primarily the responsibility of the State Governments. They have to look after it. There wilI be no difficulty in providing foodgrains to them. They are not even lifting the foodgrains that were provided to them.

श्री कुलदीप नैयर : सभापति महोदय, मंत्री जी ने वचन की बात कही है। एक वचन इन्होंने यह भी दिया था कि नेशनल काउंसिल फार सर्व शिक्षा अभियान बनेगी प्रधानमंत्री उसके सदर होंगे और जोशी जी उसके वाईस-चेयरमैन होंगे लेकिन वह अभी तक बनी नहीं। इसके बनने से यह जो एड-हॉकिज्म है, वह खत्म हो जाएगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय उसमें कई एड-हॉकिज्म नहीं है। सभी स्टेट्स में उसकी सोसायटीज़ बनी हुई है और इन सारी स्कीम्स का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें आज कोई एड-हॉकिज्म नहीं है।

श्री कुलदीप नैयर : काउंसिल तो बनी नहीं ना मैंने यह सवाल पूछा था कि काउंसिल बनी या नहीं बनी?

डा. मुरली मनोहर जोशी : काउंसिल भी बन जाएगी लेकिन यह कहना कि इसकी वजह से एड-हॉकिज्म है, यह बात गलत है।

श्रीमती सविता शारदाः सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन्होंने राष्ट्र के सभी बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचा है। मैं स्वयं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूं। ग्रासरूट लेवल पर जब हम काम करते हैं तो हमें शिक्षा में बहुत सारी कमियों के विषय में पता चलता है और अभी तक MPLAD के द्वारा हमने काफी स्कूलों के भवन निर्माण में सहायता की है। वैसे तो मंत्री जी ने बताया कि यह राज्य सरकार का विषय है लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि ग्रांटेबल स्कूल अभी सरकार नहीं दे रही है। अगर ग्रांटेबल स्कूल नहीं है तो बच्चे कहां से फीस देकर पढ़ेंगे? वे इतने गरीब हैं कि 5 रुपए, 6 रुपए तक नहीं दे पाते हैं और NGOs जो स्कूल चला रही हैं, उनकी फीस काफी ज्यादा होती है। राज्य सरकारें ग्रांटेबल स्कूल नहीं दे रही हैं, ऐसी हालत में जो मंत्री जी का सपना है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप राज्य सरकारों की बात तो राज्य सरकारों से ही पूछिए। हमारे सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा निःशुल्क है।

*426. [The questioners (Shri R.K. Anand and Jhumuk Lal Bhendia) were absent. For answer *vide* page 34—35 *infra.]*

*427. [The questioner (DR. Akhtar Hasan Rizvi) was absent. For answer *vide* page 35—36 *infra.]*